भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1734

बुधवार, 27 जुलाई, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

विशेष प्रयोजन वाहन/विशेष प्रयोजन संस्था

1734. श्री राजेन्द्र धेड्या गावित:
श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल:
श्री रमेश बिन्द:
श्रीमती अपरूपा पोद्दार:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान विशेष प्रयोजन वाहन/विशेष प्रयोजन संस्था (एसपीवी/एसपीई) के अंतर्गत परियोजनाएं आरंभ की हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान परियोजना-वार कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;
(ग) हाल के वर्षों में भारतीय विनिर्माण क्षेत्र का प्रदर्शन कैसा रहा है;
(घ) क्या सरकार द्वारा चालू खाता घाटे के स्तर और तदनुरूपी प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति के संबंध में तत्काल उपचारात्मक उपायों की आवश्यकता है; और
(ड.) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों के दौरान सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सोम प्रकाश)

(क) और (ख): जी, हां। पिछले पांच वर्षों के दौरान, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) ने राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम के भाग के रूप में तीन विशेष प्रयोजन माध्यमों (एसपीवी) को शामिल किया है, जिनका ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ग): औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) द्वारा किए गए यथा मूल्यांकित औद्योगिक विकास जिसमें पिछले पांच वर्षों के तीन क्षेत्रों अर्थात खनन, विनिर्माण तथा विद्युत शामिल हैं, का ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है।

(घ) और (ङ): भुगतान संतुलन में चालू खाता, भारत में आर्थिक गतिविधि पुनः शुरू होने के कारण वर्ष 2020-21 में जीडीपी के 0.9 प्रतिशत अधिशेष से वर्ष 2021-22 में जीडीपी के 1.2 प्रतिशत घाटे में परिवर्तित हो गया है क्योंकि देश ने महामारी से जीडीपी पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को अपनी आर्थिक रिकवरी से पूरा किया। यह चालू खाता घाटा (सीएडी) प्रारंभ में महामारी से लड़ने के लिए लगाए गए लॉकडाउन और उसके पश्चात रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण हुआ

जिसके परिणामस्वरूप दुनिया भर में आपूर्ति श्रृंखला में बाधा आई जिसके चलते वैश्विक वस्तुओं के मूल्यों में बढ़ोत्तरी हुई। चूंकि, भू-राजनीतिक संघर्ष के बने रहने से कच्चे तेल की कीमतों सहित वैश्विक वस्तु मूल्य में बढ़ोत्तरी हो रही है, ऐसे में भारत सहित निवल वस्तु आयातकों के सीएडी पर दबाव बना हुआ है।

सीएडी की वृद्धि को रोकने के लिए, सरकार ने सोने पर लगने वाले आयात शुल्क को 10.75 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया है। इसके अतिरिक्त, सीएडी को वित्तपोषित करने के लिए, आरबीआई ने देश में डॉलर अंतर्वाह को आकर्षित करने के लिए अस्थायी उपाय लागू किए हैं। इनमें घरेलू जमाराशि पर लागू होने वाले कुछ विनियमन से विदेशी मुद्रा जमाराशि में छूट देना, विदेशी जमाराशि पर ब्याज दरों को बढ़ाना, ऋण साधन में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश को आसान बनाना तथा बैंकों और अन्य उद्यमों द्वारा विदेशों से ऋण लेने में लचीलापन बढ़ाना शामिल है।

*****

अनुबंध-I

दिनांक 27.07.2022 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1734 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

क्र.सं.	एसपीवी का नाम	शामिल करने की तिथि	परियोजना	इक्विटी संरचना (%)		उद्देश्य	वित्त वर्ष				कुल
				केंद्र (एनआईसीडीआईटी)	राज्य		2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (22.07.22 तक)	
1	सीबीआईसी पोन्नेरी इंडस्ट्रियल टाउनशिप लिमिटेड	30.07.2022	चेन्नई बेंगलुरु औद्योगिक कॉरिडोर (सीबीआईसी) के तहत तमिलनाडु के पोन्नेरी में औद्योगिक नोड	50%	50%	इक्विटी	-	2.50	-	-	2.50
2	केरल औद्योगिक कॉरिडोर विकास निगम लिमिटेड	21.04.2021	कोयंबटूर के रास्ते कोच्चि तक सीबीआईसी के विस्तार के तहत केरल के पलक्कड़ में औद्योगिक नोड	50%	50%	इक्विटी	-	-	2.50	-	2.50
3	राजस्थान औद्योगिक कॉरिडोर विकास निगम लिमिटेड	15.03.2022	दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर (डीएमआईसी) के तहत राजस्थान में खुशखेड़ा-भिवाड़ी-नीमराना निवेश क्षेत्र (केबीएनआईआर) और जोधपुर-पाली-मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र (जेपीएमएआई) में औद्योगिक नोड	49%	51%	इक्विटी	-	-	-	4.90	4.90
	कुल						**-**	**2.50**	**2.50**	**4.90**	**9.90**

(स्रोत: राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास और कार्यान्वयन न्यास)

अनुबंध-II

दिनांक 27.07.2022 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1734 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पिछले पांच वर्षों हेतु सामान्य आईआईपी और क्षेत्रगत सूचकांक					
	2017-18	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22***
खनन	104.9	107.9	109.6	101.0	113.3
विनिर्मण	126.6	131.5	129.6	117.2	131.0
विद्युत	149.2	156.9	158.4	157.6	170.1
सामान्य आईआईपी	125.3	130.1	129.0	118.1	131.6

*** आंकड़ें अनंतिम हैं।**

पिछले पांच वर्षों हेतु सामान्य आईआईपी और क्षेत्रगत विकास दर (प्रतिशत में)					
	2017-18	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22***
खनन	2.3	2.9	1.6	-7.8	12.2
विनिर्माण	4.6	3.9	-1.4	-9.6	11.8
विद्युत	5.4	5.2	1.0	-0.5	7.9
सामान्य	4.4	3.8	-0.8	-8.4	11.4

*** आंकड़ें अनंतिम हैं।**

(स्रोत: आर्थिक सांख्यिकी विभाग, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय)

****